

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवाएं,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक/०अक्टूबर, 2007

विषय:-मै० जेमसन्स हेल्थ केंद्र प्रा०लि० को तहसील रुड़की के ग्राम मंडावर में फार्मास्युटिकल्स उद्योग की स्थापना हेतु कुल 0.1740 है० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०- 1447/भूमि व्यवस्था-मूक० दिनांक 04 जनवरी, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० जेमसन्स हेल्थ केंद्र प्रा०लि० को तहसील रुड़की के ग्राम मंडावर में फार्मास्युटिकल्स उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुसूचन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा- 154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम मंडावर के खाता सं० 99 के खसरा सं० 334 रकबा 0.1740 है० भूमि खातेदार प्रमु पुत्र कन्दू निवासी मंडावर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की के नाम वर्ग 1 (क) संकगणीय भूमिधरी के दर्ज अभिलेख हैं, को फार्मास्युटिकल की स्थापना हेतु भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल रा ज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे

भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडी)-2005 के अन्तर्गत GIDCR में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

8- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- इकाई का प्रस्तावित उत्पाद फार्मा प्रोडक्ट (टेबलैट, कैप्सूल) है, जो भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 1(10)/2001 एनईआर दिनांक 6 जनवरी, 2003 के अनुसार थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत है। इकाई की स्थापना होने पर इकाई को भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। परन्तु इकाई को 31-03-2010 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।

10- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के वंशेगारों को 70 प्रतिशत से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र प्रोडक्ट के क्रियाकलापों की स्थापना हेतु किया जायेगा।

12- प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

13- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व इंग कन्ट्रोलर से इंग लाइसेन्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0एस0नपलच्याल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल गण्डल, पौड़ी।
- 4- श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर, गै0 जेमरान्स हेल्थ केयर प्रा0लि0, नि0 311 विष्णुपुरी कालोनी, सिविल लाइन्स, गोनडा, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिजुल कुमार जोशी)  
अपर सचिव।